

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
बहुलम भवन भोपाल-462004

दिनांक: 13.11/10/3/2000

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2000

- 1 - रागरत जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश.
- 2 - रागरत वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश.

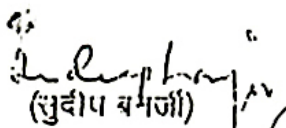
विषय - वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण।

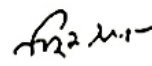
---0---

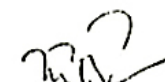
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन को रोकने की दृष्टि से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि -

1- जिले में वर्तमान में स्वीकृत रागरत उत्खनन तीन प्रकरणों का जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारियों द्वारा समीक्षा कर यह पुष्टि कराई जायेगी कि जिले में कोई भी उत्खनन कार्य अनियमित रूप से वन क्षेत्र में संचालित नहीं है।

2- जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि वन क्षेत्रों में रागरत सरकार को स्वीकृत के बिना, उत्खनन के लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया है और न ही बिना पट्टे के कोई अवैध उत्खनन कार्य चल रहा है। यह कार्य एक निश्चित समयवाचि अर्थात् दिनांक 31-5-2000 तक पूरा किया जाए।


(सुदीप बहजगी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग


(श्री.के.साहा)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग


(मला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
राजरत विभाग

संख्या: एन/माक/13 S C /10/3/2000

गोपाल, दिनांक 2, 11 मार्च, 2000

सर्वों को,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग गोपाल
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग गोपाल
- 3- समस्त संगणायुक्त, मध्य प्रदेश.
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश गोपाल.

कृपया प्रारंभ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रगणित ।

(P-3-C)

(जी.ए. गिन्जेल)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग